पड़ोसी देश में हलचल : मालदीव समस्या पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- निरुपमा सुब्रमण्यम (संपादक)

31 अक्टूबर, 2018

''मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने 17 नवंबर को अपना पद संभाला और चीन समर्थक यामीन को हार का सामना करना पड़ा, जिससे एक तरफ तो भारत ने राहत की सांस ली है, मगर दूसरी तरफ भारत को हिंद महासागर द्वीपसमूह में हो रही हलचल ने भी चिंता में डाल रखा है।''

श्रीलंका में पिछले तीन वर्षों से चली आ रही राजनीतिक शांति पिछले हफ्ते एकदम से भंग हो गयी, साथ ही एक अन्य हिंद महासागर देश और भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों में शामिल मालदीव अभी तक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जहाँ राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम सोलिह से हार का सामना करना पड़ा।

यामीन ने शुरुआत में हार मान ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने मतदान में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नतीजे को चुनौती दी और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को रिश्वत दी गई है। कुछ हफ्ते पहले पांच सदस्यों वाले आयोग में से चार ने यह आरोप लगाते हुए देश छोड़ दिया कि अगर वे यहाँ रहे तो उनके जीवन को खतरा है। हांलाकि, मालदीव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द करने की मांग करने वाली यामीन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सोलिह ने 17 नवंबर को शपथ ग्रहण किया।

इसके अलावा, मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद की 13 साल की कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। सजा तभी तक के लिए स्थगित है जब तक कि सरकारी वकील की अपील पर उनके दोष की समीक्षा नहीं हो जाती है। नशीद, जो 2016 से लंदन और कोलंबो में निर्वासन में रह रहे हैं, अब गिरफ्तारी के डर के बिना गुरुवार को माले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं।

संयुक्त विपक्ष ने पीपुल्स मजलिस या संसद पर अपनी पकड़ को भी मजबूत कर लिया है। इस महीने, देश की शीर्ष अदालत ने 12 सांसदों की सदस्यता बहाल कर दी है जिन्हें पिछले साल दोषी पाए जाने के बाद यामीन की प्रगतिशील पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा बलों ने यामीन को सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अयोग्य संसद सदस्यों को संसद में प्रवेश करने से रोका और इस साल फरवरी में, मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य न्यायाधीशों (नशीद के पक्ष में जाने के कारण) और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

भारत, चीन, मालदीव

श्रीलंका की तरह ही भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता को मालदीव में भी बखूबी देखी जा सकती है, कुछ लोग तो यामीन-सोलिह राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन भारत-चीन प्रॉक्सी युद्ध के रूप में भी करते हैं। अपने अभियान भाषणों में, सोलिह ने चीनी ऋण जाल के कई उदहारण दिए थे और देश में चीनी विकास परियोजनाओं को भूमि हरण के रूप में वर्णित किया।

फरवरी में जारी किये गये एक अध्ययन में, मुंबई स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस ने तीन सबसे बड़ी चीनी परियोजनाओं का जिक्र किया, जिसमें पहला माले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास है, दूसरा एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, जो हूलहुले द्वीप को जोड़ता है जिस पर राजधानी माले में हवाई अड्डा स्थित है और तीसरा एक पुनर्स्थापित द्वीप पर मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और इन सभी में अनुमानतः लागत 1.5 बिलियन डॉलर की आएगी।

नशीद का हवाला देते हुए, अध्ययन में कहा गया है कि कानून में बदलाव के बाद, चीन ने द्वीपसमूह में 1,200 द्वीपों में से 17 को लीज यानि पट्टे पर ले रखा था, इसके अलावा होटल, एयरलाइंस, बिजली, पानी और सीवेज उपचार संयंत्रों के विकास भी इसमें शामिल है। वर्ष 2017 में मालदीव में चीनी पर्यटक 300,000 के आंकड़े को पार कर चुके थे, जो वर्ष 2009 में लगभग 60,000 ही थे। यामीन सरकार ने पिछले साल संसद के माध्यम से चीन के साथ एक विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौता अर्थात फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी किया था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने सोलिह के जीत का क्यों स्वागत किया, भारत को यह उम्मीद है कि नया परिवर्तन चीन से जुड़ी परियोजनाओं में से कुछ को ठण्डे बस्ते में डाल देगा। हांलाकि, नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने चुनाव के बाद से कोई साक्षात्कार नहीं दिया है, लेकिन सोलिह की जीत के बाद नशीद ने कहा कि कुछ चीनी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

देखा जाये तो श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता सरकार या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) ने चीन के परियोजनाओं की समीक्षा करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें अपने वादे को निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

इसलिए मालदीव में राजनेताओं को भी सवाधानी बरतनी होगी। श्रीलंका में, एनयूजी ने गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद बंदरगाह शहर के पुनर्विचार को मंजूरी दे दी और हंबनटोटा बंदरगाह में चीन को काफी हिस्से बेच दी थी।

सोलिह की जीत के तुरंत बाद, शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर एशिया-पैसिफिक स्टडीज के निदेशक झाओ गंचेंग ने द ग्लोबल टाइम्स को बताया कि उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान चीन पर अव्यवहारिक शब्दों के बावजूद, वह बीजिंग से दूर नहीं हो पाएंगे।

चीन-मालदीव सहयोग पारस्परिक है और आधारभूत परियोजनाएं लोगों के जीवन और विकास में सुधार कर सकती हैं। मालदीव के लिए पूरी तरह से भारत की ओर दिलचस्पी दिखाना इस बात की गारंटी नहीं देता कि नई दिल्ली मालदीव के विकास में पूरी तरह से योगदान देगी, जिसकी उम्मीद माले ने लगा रखी है।

सोलिह कार्यालय मानता है, वह संतुलित नीतियों का पलान करेगा जो राष्ट्रीय हितों की सेवा करेगी। चीन ने मालदीव का सहयोग करने वाले अन्य देशों का कभी भी विरोध नहीं किया है, लेकिन चीन उम्मीद करता है कि यह चुनाव परिणाम उनके लिए उल्टा ना साबित हो।

आगे की चुनौतियां

सोलिह के लिए मालदीव में स्थिति ठीक वैसी ही है जैसा वर्ष 2015 में मैत्रीपाला सिरिसेना के लिए श्रीलंका में थी। सोलिह नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और उनकी उम्मीदवारी जुमहोरे पार्टी, अधलाथ पार्टी और पीपीएम के मौमून अब्दुल गयूम गुट द्वारा समर्थित थी।

विविध विचारधाराओं के बावजूद, जो चीज उन्हें एक साथ लाया वह यामीन को हटाने की आम इच्छा थी। लेकिन अब उनके समक्ष चुनौती एक साथ खड़े रहना है। नशीद अपनी एकता बनाने में क्या भूमिका निभाएंगे, वह देखना महत्वपूर्ण होगा।

सहयोगियों के बीच कैबिनेट पदों के लिए बातचीत चल रही है। यामीन के साथ सरकार कैसे काम करती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निश्चितरूप से मालदीवियन राजनीतिक कैलेंडर में अगली बड़ी घटना 2019 का संसदीय चुनाव साबित होगा।

GS World टीम...

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मालदीव में सोमवार को लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक उठापटक थम गई। मालदीव ने अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है।
- यहां विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम को हरा दिया।
- सोहिल की जीत के साथ ही भारत को बिगड़े संबंधों को सुधारने का एक बड़ा मौका मिल गया है। मालदीव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह पलट गए हैं।
- चीन वहां अपना सामरिक विस्तार बहुत तेजी से कर रहा है। ऐसे में ये नतीजे चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं।

मालदीव भारत के लिए क्यों है अहम?

- मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का देश है, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है।
- मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्बाध रूप से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है।
- चीन 10 साल पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों को भेजना शुरू कर चुका था। अदन की खाड़ी में ऐंटी पायरेसी अभियानों के नाम पर मालदीव इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में धीरे-धीरे काफी अहम बन गया है।
- दक्षिण एशिया की मजबूत ताकत होने और हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते भारत को मालदीव के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है।
- मालदीव में चीन की बड़ी आर्थिक मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता की बात है। कहा जाता है कि मालदीव को बाहरी मदद का 70 फीसदी हिस्सा अकेले चीन से मिलता है।
- कई लोगों का मानना है कि मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने किया था। ऐसे में इस राजनीतिक संकट पर भारत की चौकन्नी नजर है।
- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की एमडीपी समेत विपक्ष का समर्थन करने वाली मालदीव की बड़ी आबादी चाहती है कि भारत इस संकट में अपने पड़ोसी देश की मदद करे और यामीन के खिलाफ कार्रवाई करे।
- मालदीव SAARC का भी सदस्य है। ऐसे में इस इलाके में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव को अपने साथ रखना जरूरी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उड़ी में किए गए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले SAARC सम्मेलन का भारत द्वारा बहिष्कार करने के आह्वान पर मालदीव एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस आह्वान पर अनिच्छा जताई थी।

GS World Committed to Excellence

- यामीन के शासनकाल में मालदीव में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सीरिया में लड़ाई के लिए मालदीव से कई लड़ाके गए थे। अपने पड़ोसी देश में कट्टरपंथ का बढ़ना भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
- मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है। 1965 में आजादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था। बाद में भारत ने 1972 में मालदीव में अपना दूतावास भी खोला।
- मालदीव में करीब 25 हजार भारतीय रह रहे हैं। हर साल मालदीव जाने वाले विदेशी पर्यटकों में 6 फीसदी भारतीय होते हैं।
- मालदीव के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिकों द्वारा उच्च शिक्षा और इलाज के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की मांग बढ़ती जा रही है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'फ्रेंडशिप ब्रिज' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) इस ब्रिज को मालदीव में चीन द्वारा बनाया गया है।
(b) यह ब्रिज मालदीव की राजधानी माले तथा हुलहुले द्वीप को जोड़ता है।
(c) इस ब्रिज में भारत का भी योगदान है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में इब्राहिम सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
2. माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास चीन द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

3. ''भारत-चीन प्रॉक्सी युद्ध'' के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?

(a) भारत और चीन के मध्य ट्रेड वार
(b) भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर विवाद
(c) यामीन-सोलिह राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन
(d) मालदीव और चीन के मध्य चुनाव में सहयोग

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पिछले कुछ वर्षों से चीन-मालदीव संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे, परंतु हाल में (वर्ष 2018) मालदीव में सम्पन्न हुए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद चीन-मालदीव संबंध पर विपरीत प्रभाव तथा भारत-मालदीव संबंध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विश्लेषण कीजिए। (शब्द-250)

नोट :
30 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) और 2(a) होगा।